भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1870
उत्तर देने की तारीख 03 जुलाई, 2019

भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन

1870. श्री अनिल फिरोजियाः

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम लिमिटेड में भारत नेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आंतरिक क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना की रिपोर्ट किस समय तक अनुमोदित होने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में निधि कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर
संचार, विधि और न्याय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से (घ) भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन मध्य प्रदेश सहित देश की सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2,50,000) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। परियोजना के चरण-I को मध्य प्रदेश में कार्यान्वित करने का कार्य भारत संचार निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

भारतनेट परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने दिनांक 19.07.2017 को भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन की संशोधित कार्य-नीति को अनुमोदित किया। संशोधित कार्य-नीति के अनुसार देश की शेष 1,50,000 (लगभग) ग्राम पंचायतों में इसके चरण-II को तीन मॉडलों अर्थात राज्य आधारित मॉडल, निजी क्षेत्र और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) मॉडल के आधार पर कार्यान्वित किया जाना है।

दूरसंचार आयोग (जिसे अब डिजिटल संचार आयोग कहा जाता है) द्वारा प्रदान किए गए अनुमोदन के अनुसार मध्य प्रदेश में परियोजना के चरण-II का कार्यान्वयन बीएसएनएल के माध्यम से किया जा रहा है।

*****